कैट के राष्ट्रीय सचिव ने जीएसटी की कमियों को दूर करने की मांग की

जीएसटी में 1100 बार संशोधन, पर व्यापारी को गलती सुधारने का नहीं दिया जाता मौका

बिजनेस रिपोर्टर | सूरत

जीएसटी देश का सबसे बड़ा खराब टैक्स कलेक्शन सिस्टम है। सबसे जटिल कर प्रणाली है। जीएसटी के चार साल बाद व्यापारी इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि यह वह जीएसटी नहीं है जिसके बारे में हमसे बात की गई थी। सूरत दौरे पर आए सूरत दौरे पर आए कैट (कंफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स एसोसिएशन) के अध्यक्ष प्रवीण खंडेलवाल ने ये बातें कहीं। उन्होंने कहा कि जीएसटी के लिए सभी राज्यों की सरकारें दोषी हैं, क्योंकि किसी ने भी जीएसटी की सरल प्रणाली के लिए बात नहीं की है।

खंडेलवाल ने कहा कि जीएसटी के कारण व्यापारियों की मुश्किलें बढ़ी हैं। इसलिए जीएसटी काउंसिल में इसकी समीक्षा कर कमियों को दूर करना चाहिए।

कपड़ा और फुटवेयर पर 5 प्रतिशत जीएसटी रखने की मांग

देश में 85 प्रतिशत लोग 1000 रुपए से सस्ते कपड़े और फुटवेयर पहनते हैं। इसलिए 1000 से नीचे की कीमत वाले कपड़े और फुटवेयर पर 5 प्रतिशत ही जीएसटी रहे इसके लिए कैट द्वारा केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण और पीयूष गोयल से मांग की जाएगी।

ई-कॉमर्स वेबसाइट पर हो रहा है अवैध कारोबार

प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि ई-कॉमर्स देश का भविष्य का व्यापार है, लेकिन इसमें नियमों का उल्लंघन हो रहा है। ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा बाजार में मोनोपोली बनाई जा रही है। इसमें बैंक, ब्रांड की भी सांठगांठ होती है। ई-कॉमर्स पोर्टल पर अवैध गतिविधियां हो रही हैं।

कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स एसोसिएशन के राष्ट्रीय सचिव ने कहा कि जीएसटी में चार साल में 1100 से ज्यादा बदलाव किए गए हैं। अगर व्यापारी से कोई भूल हो जाए तो जीएसटी में उस भूल को सुधारने का मौका नहीं दिया जाता है। अधिकारियों को अधिक अधिकार दिए गए हैं। अगर व्यापारी जीएसटी में गलती करता है तो उसका नंबर ब्लॉक कर दिया जाता है। जीएसटी में स्पष्टीकरण का प्रावधान नहीं है। इज ऑफ डूइंग की बात तो होती है लेकिन जीएसटी में यह संभव नहीं है। हम जीएसटी काउंसिल से मांग कर रहे हैं कि जीएसटी की तुरंत समीक्षा की जाए। हम डिजिटल भुगतान के मुद्दे पर भी अभियान चलाएंगे।